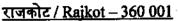


## ः : आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, यस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्कःः O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in DIN20230264SX0000913707



अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.

GAPPL/COM/STP/2090/2022

मल आदेश सं 🖊 Ö.I.O. No. 169:/SERVICE TAX/DEMAND/2021-22 दिनांक/Date 21-01-2022

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

## BHV-EXCUS-000-APP-041-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order: 13.02.2023

В

जारी करने की तारीख / Date of issue:16.02.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर /वस्तु एवंसेवाकर , राजकोट / जामनगर / गांधीक्षाम। द्वारा उपरिविधित जारी मूल आदेश से स्जित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

अपीसकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of theAppellant&Respondent :-

M/s. Beena Lalitkumar Sharma( M/s Naman Collection), 320, Evasurabhi Road Opp. Aksharwadi, Waghawadi Road, Bhavnagar-364001

इस आदेश(अपीन) से व्यक्ति कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपीन दावर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क , कन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं संवाकर बर्पालीय न्यायाधिकरण के प्रति बर्पाल, कन्द्रीय उत्पाद शुल्क ब्रोधेनियम , 1944 की झारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त ब्रिधिनियम, 1994 की झारा 86 के बंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/ (A)

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मुल्बांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरेम, नई विल्ली, को की जानी चाहिए !/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, ,दितीय तल, बहुमाली भवन अलावा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्न टिंकू-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग , ज्याज की माँग और सगाया प्रया जुमीना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक ब्रुवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, ज्ञान क्षमण 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क को शुल्ताल, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित इपट का शाखा के सहायक रिजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आवेश (स्टे ऑडर) के लिए आवेदन-एन के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करेना होगा।/ , (iii)

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penality/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

अपीलीय त्यायाधिकरण के समक्ष अपील, विश्व अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग , ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, उपए 5 लाख वा उससे कम, 5 लाख देगए या 50 लाख देगए तक अथवा 50 लाख देगए से अधिक है तो कम्या: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जुमा शुरूक की प्रति संलघ करें। निर्धारित शुरूक का घुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकर की सहायक रिजिस्टा के नाम से किसी भी सार्विजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक बार्य जाना चाहिए। संबंधित इएस्ट का सुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकर की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्ट ऑडर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुरूक जेमा करना होगा।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of companied by a fees of Rs. 5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs out not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs. 10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(i)

(ii)

मारत सरकार कोपूनीयन आवेदन :

मारत सरकार कोपूनीयन आवेदन :

Revision application to Government of India:

इस अवेदम की पुनरीक्षणवाचिका निमालिक्षित मामनो में, केंद्रीय उत्पाद शुक्क अविनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपुरंतुक के अंतर्गतज्ञवर सचिव,
भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, की किया

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit,
Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to subsection (1) of Section-35B ibid: (C)

यदि माल के किसी नुक्सान के मामले में, जहां नुक्सान किसी माल को किसी कारखाने से अंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंडार गृह से दूसरे अंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के नुक्सान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के खुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना मारत के बाहर, नेपाल या भुटान को माल निर्यात किया क्या है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुन्क के भूगतान के लिए वो ड्यूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की नई है और ऐसे आदेश को अपुक्त (अपीन) के द्वारा, वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारी व अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है। Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act, or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपन्न सक्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुक्क (वर्षील) नियमावली 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त जावेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की प्रतियां सलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुक्क जाविनियम, 1944 की धारो 35-EE के तहत निर्धारित शुक्क की बदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति सलग्न की निर्धार की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIQ and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुस्क की बदावगी की जानी चाहिए। जहाँ संबंध रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान रूपये जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

यदि इस लादेश में कई मूल जादेशों का समावेश है तो प्रयोक मूल आदेश के लिए शुल्क का मुगतान, उपर्यक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बनने के लिए यथास्थिति क्पीलीय नयाधिकरण को एक अपनेद में से से कर के एक आवेदन किया जाता है। / In case if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for (D)

यवासंशोधित त्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का त्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीमीव त्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. **(F)** 

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in. (G)



## :: अपीन आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Beenaben Lalitkumar Sharma, Bhavnagar (hereinafter referred to as "Appellant") has filed the present Appeal against Order-in-Original No. 169/SERVICE TAX/DEMAND/2021-22 dated 21.01.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division, Bhavnagar-1 (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- 2. The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department shared the third party information/ data based on Income Tax Returns/ 26AS for the Financial year 2014-15 of the Appellant. Letter dated 15.07.2020 was issued by the Jurisdictional Range Superintendent requesting the Appellant to provide information/documents viz. copies of I.T. Returns, Form 26AS, Balance Sheet (including P&L Account), VAT/ Sales Tax Returns, Annual Bank Statement, Contracts/ Agreements entered with the persons to whom services provided etc. for the Financial year 2014-15 to 2017-18 (upto June-2017). However, no reply was received from the Appellant.
- 3. In absence of data/information, a Show Cause Notice dated 13.08.2020 was issued to the Appellant, demanding Service Tax and cess to the tune of Rs. 12,295/- under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') alongwith interest under Section 75 of the Act. It was also proposed to impose penalties under Section 78, 77(2) and 77(1)(c) of the Act upon the Appellant.
- 4. The above Show Cause Notice was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order who confirmed Service Tax demand of Rs. 12,295/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act, imposed penalty of Rs. 12,295/- under Section 78 of the Act, imposed penalty of Rs. 5,000/- each under Section 77(1)(a), 77(2) and 77(1)(c) of the Act.
- 5. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal on various grounds that the Appellant is engaged in the business of trading of furniture, electrical goods and household items etc. and also providing tuitions to the students. The demand confirmed on value of Rs. 89,400/- is nothing but the income from tuition. Due to change of address she was unable receive the Show Cause Notice and other related correspondence. She has been denied fair opportunity of being heard and thus there is violation of natural justice. The Department has not analysed the grounds for invocation of extended period viz. absence of Service Tax registration and non filing of returns but mechanically construed the same to constitute suppression of facts with intention to evade payment of Service Tax. She relied on the decision in the case of Pushpam maceutical Co. Vs Commissioner of Central Excise, Bombay reported as 1995

1/21

(78) ELT 401 (SC), Anand Nishikawa Co. Ltd. V. Commissioner of Central Excise, SOTC Travels Services Pvt. Ltd. V. Principal Commissioner, Central Excise reported as 2021 SCC Online CESTAT 2574, Uniworth Textile Ltd. V. Commissioner of Central Excise, Raipur - 2013 (288) ELT 161 SC, Bharat Hotels Ltd. V. Commissioner of Central Excise, Delhi, Delhi International Airport Ltd. Vs. Commissioner of CGST, Delhi - 2019 (24) GSTL 403 (Tri.-Del.). No mala fides can be attributed in view of absence of Service Tax registration and non filing of ST-3 returns. They relied on the decision of M/s. Suchak Marketing Pvt. Ltd. V. Commissioner of Service Tax, Kolkata - 2013 (6) TMI 641.

- 5.1 The Service Tax cannot be automatically/ mechanically determined on the basis of Income Tax Return and Form 26AS and they relied on the decision in the case of Cosmic Dye Chemical V. Collector of Central Excise reported as 1994 (95) STC 604 SC, Commissioner of Service Tax, Ahmedabad V. Purani ADS Pvt. Ltd. 2010 (19) STR 242 (Tri.-Ahmd.), M/s. Reliance Industries Ltd. V. Commissioner of Central Excise, Rajkot- 2008 (10) STR 243 (Tri.-Ahmd.), Synergy Audio Visual Workshop V. Commissioner of Service Tax, Bangalore 2008 (14) STT 321. The service is exempted as per Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012 and the Adjudicating Authority has mechanically charged Service Tax. The aggregate value of all taxable services in the preceding financial year 2013-14 was Rs. 1,18,800/-.
- 6. The matter was posted for hearing on 01.02.2023. Shri Lalit Sharma, husband of the appellant appeared for personal hearing and submitted that they did not receive any letter, Show Cause Notice, personal hearing notice from the department. Even Order-in-Original dated 21.01.2022 was handed over to them on 31.05.2022 after calling them to the office of CGST. It may be seen from the profit and loss account that income of Rs. 89,400/- is tuition income and Rs. 10,077.75 is Kasar income. In view of this, he requested to set aside the exparte Order-in-Original.
- 7. I have carefully gone through the case records, impugned order and appeal memorandum filed by the Appellant. I find that the issue to be decided in the case on hand is whether the activity carried out by the appellant is liable to Service Tax or otherwise.
- 8. I find that Show Cause Notice had been issued without verifying any data or nature of services provided by the Appellant as the same had been issued only on the basis of data received from the Income Tax department and the Adjudicating Authority has confirmed the demand of Service Tax vide impugned order. It is the contention of the Appellant that due to change of address they have not received any letter, Show Cause Notice or personal hearing letters from Department. The impugned order was handed over to them on 31.05.2022

A.V

after calling her to the office of CGST.

- It is the contention of the Appellant that they are engaged in the business of trading of furniture, electrical goods and household items etc. and also providing tuitions to the students. The demand confirmed on value of Rs. 89,400/- is nothing but the income from tuition which is exempt as per Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012. It is their contention that the income from tuition during the year 2013-14 was Rs 1,18,800/-. I find that as per the documents viz. Income Tax Returns, Balance sheet, profit & loss account, it is on record that the Appellant is engaged in sale purchase business in the name and style of Naman Collection. There is mention of opening stock, sales, purchase and closing stock details in the profit & loss account produced by the Appellant. In income tax return, there is mention of sale of goods and sale of service in Part-A-P&L and the figures are tallied with the figures of sale of goods and sale of service i.e. other income mentioned in the Profit & Loss Account. The Appellant is also having income from tuition of Rs. 89,400/- and Kasar income of Rs. 10,077.75 total Rs. 99,478/- which is below threshold limit of Rs. 10 Lakh as per Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012. On verification of profit and loss account for the year 2013-14 and other income mentioned in income tax return, there is mention of tuition income of Rs. 1.18.800/- which is also below the threshold limit. Thus, I find that the taxable value on which Service Tax is demanded is within the threshold limit as prescribed under Notification No.33/2012-Service Tax dated 20.06.2012 and thus I am of the considered view that the Appellant is eligible for benefit of the said Notification and is not liable to Service Tax.
- 10. In view of discussions and finding, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the Appellant.
- 11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।
- 11. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

<u>}</u>

(शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh),

आर, बेस. बोरीचा / R. S. BORICHA आयुक्त (अपीस)/Commissioner (Appeals)

अधीक्षक / Superintendent के. व. एवं सेवा कर अर्थास्स, राजकोट

By R.P.A.D.CGST Appeals, Rajkot

To

M/s. Beenaben Lalitkumar Sharma, M/s. Naman Collection, 320,

Evasurabhi Road, Opp.: Aksharwadi, Waghawadi Road,

Bhavnagar-364001.

सेवा में,

मे बीनाबेन ललितकुमार शर्मा, मे. नमन कलेक्शन, 320, ईवासुरिम रोड, अक्षरवाडी के सामने, वाघावाडी रोड, भावनगर-364001 ।



## प्रतिलिपि :-

- मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर मण्डल-1 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5) गार्ड फ़ाइल।

